"ग्रामीण विकास में रोजगार कार्यक्रमः एक अध्ययन"

डॉ0 विवेक कुमार मिश्र
सहायक आचार्य,
वाणिज्य विभाग,
हण्डिया पी0जी0 कालेज,
हण्डिया प्रयागराज।

भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र की प्रधान अर्थ व्यवस्था है क्योंकि देष की लगभग 68.82ः जनसंख्या गांवो में निवास करती है। यही नहीं सकल घरेलू उत्पाद का 33ः तथा निर्यात आय का 24ः तथा करो से प्राप्त कुल आय का 46ः भाग ग्रामीण क्षेत्रो से होता है। जिसके कारण देष के विकास में ग्रामीण क्षेत्रो के महत्वपूर्ण भूमिका स्वतः स्पश्ट होती है। अतः ग्रामीण क्षेत्रो को विकास के मुख्य धारा में षामिल करके ही समग्र व वास्तविक विकास सम्भव हो सकता है क्योंकि ग्रामीण विकास ही समग्र विकास की कुंजी है।

ग्रामीण विकास अत्यंत आवष्यक भारत के दृश्टिकोण से इसलिए भी है कि भारत की आत्मा गांवो में बसती हैं। अतः ग्रामो का विकास सुनिष्चित करने के लए सर्वप्रथम बेरोजगारो की संख्या कम से कम करने का प्रयास किया जाना अनिवार्य रूप से परिलक्षित होता है। इस मूलमंत्र को दृश्टिगत रखते हुए यह अवष्यम्भावी हो जाता है कि देष के गांवो को विकास पथ पर अग्रसर किया जाए। विकास का मूलभूत उद्देष्य एक ऐसी समतावादी समाज व्यवस्था को सुनिष्चित करना है जहां पर सभी व्यक्ति समान हो सभी के लिए समानरूप से अवसरो की समानता विद्यमान हो तथा विभिन्न क्षेत्रो समाज एवं वर्ग आदि में लकीरे न हों।

भारत में ग्राम विकास की चेतना का सूत्रपात राश्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। उनका कहना था कि "दिल्ली भारत नहीं है भारत तो गांव में बसता है" यदि हम भारत को विकसित करना चाहते है तो गांवो को सर्वप्रथम विकसित करना होगा, जिसमें षिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास एवं विकास को मुख धारा से जोड़ना होगा, ताकि सर्वप्रथम गांव को विकासित पथ पर अग्रसर कर भारत को विकसित किया जाना सम्भव हो सके।

ग्रामीण विकासः— ग्रामीण विकास एक व्यापक षब्द है यह मुख्यतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अघटको के विकास पर ध्यान केद्रित करने पर बल देता है जो मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वागीण विकास में पीछे रह गये है। भारत के विकास के लिए जिन क्षेत्रो में नयी और सार्थक पहल करने की आवष्यकता है वह है भारत की ग्रामीण क्षेत्र। प्रायः ग्रामीण विकास से अभिप्राय होता है कि ग्रामीण जनसमुदाय के जीवन स्तर में सुधार कैसे लाया जाए तथा यह भी समझा जा सकता है कि ग्रामीण विकास ग्रामीण क्षेत्रो में निवास कर रही न्यूनतम आय वाली जनसंख्या के रहन—सहन के स्तर को उठाने की प्रक्रिया है। ग्रामीण विकास के अन्तर्गत वे समस्त कार्यक्रम सम्मिलित किये जाते है जो ग्रामीण जनो के जीवन से जुड़े होते है, जो उनके प्रत्येक क्रिया का आधार हो सकता है। ग्रामीण विकास को एक विचार धारा के रूप में विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं की गयी है। पूर्व में ग्रामीण विकास को कृशि के समानार्थी माना गया अर्थात कृशिका विकास ही ग्रामीण विकास है तथा कृशि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, किन्तु

अब ग्रामीण विकास को कृशि से अलग तथा उससे बढ़कर माना गया है साथ ही साथ राश्ट्रीय विकास योजनाओं में इसे विस्तृत तथा उदार परिप्रेक्ष्य के रूप में देखा गया है।

रोजगार कार्यक्रमः–

1. **स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना**– यह योजना गांव के गरीब जनता के लिए स्वरोजगार की एक एकल योजना है जिसका षुभारम्भ 1 अप्रैल 1999 को प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना में पूर्वरत स्वरोजगार कार्यक्रमो की षक्तियो एवं कमजोरियों का ध्यान रक्खा गया है।

2. **जवाहर ग्राम समृद्धि योजना**ः–इस योजना का मुख्य उद्देष्य गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्थायी परिसम्पत्तियों सहित मांग प्रेरित बुनियादी ढांचे के निर्माण तथा ग्रामीण क्षेत्रो में गरीब रोजगार, अल्परोजगार वाले व्यक्तियों को सृदृढ़ बनाना था।

3. **रोजगार आष्वासन योजना**– यह योजना 2 अक्टूबर 1993 को विभिन्न राज्यों में लागू की गयी थी जिसका उद्देष्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीणो को मंदी के दौरान भी श्रम कार्यो द्वारा अतिरिक्त मजदूरी, रोजगार अवसरो को प्रदान करना था।

4. **ग्रामीण रोजगार पीढ़ी योजना**– यह योजना 1995 में प्रारम्भ की गयी। इसका उद्देष्य था कि ग्रामीण क्षेत्रो में खादी एवं ग्रामीण उद्योग को स्थापित कर रोजगार सृजन किया जाए तथा ग्रामीणो को प्रषिक्षित किया जाए।

5. **मनरेगा योजना**– यह योजना 2 फरवरी 2006 से लागू की गयी, इस योजना का उद्देष्य एक वित्तीय वर्श में 100 दिन की प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को रोजगार की गारंटी देती है।

6. **प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम**– यह योजना 15 अगस्त 2008 को लागू की गयी। इसका उद्देष्य सब्सिडी युक्त साख उपलब्ध कराकर सूक्ष्म एवं लघुउद्योग की स्थापना कर रोजगार का निर्माण करना।

7. **छण्ण्स्ण्डण्योजना–** स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना को राश्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिषन के रूप उमें पुर्नगठित किया गया जिसका नया नाम अब ''आजीविका'' कर दिया गया है। इस योजना में रोजगार में सहायता प्रदान करना, कौषल विकास के लिए अवसर उपलबध कराना, ऋण और सब्सिडी देना, स्वरोजगार में सहायता करना, उत्पादन के विपणन के अवसरो का का विकास करना, गरीबो की आर्थिक स्थिति में सुधार करना।

8. **प्रधानमंत्री कौषल विकास योजना**– यह योजना भारत सरकार ने जुलाई 2015 में षुरू किया था, इस योजना के अनुसार 2020 तक एक करोड़ युवाओं को प्रषिक्षण देने की योजना बनाई गयी थी। इसका मुख्य उद्देष्य देष में सभी युवा वर्ग को संगठित करके उनके कौषल को निखार कर उनकी योग्यतानुसार रोजगार उपलब्ध कराना।

9. **मुद्रा योजना**– इस योजना की षुरूआत 8 अप्रैल 2015 को की गयी थी। इस योजना का मुख्य उद्देष्य था कि स्वरोजगार हेतु तीन माध्यम से ऋण प्रदान किया जाय– षिषु, किषोर और तरूण। ताकि वित्त की सहायता से लघु एवं मध्यम उद्योगो को स्थापित कर ग्रामीण बेरोजगारी को दूर किया जा सकें।

निश्कर्श :– ग्रामीण विकास की संकल्पना एक प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है। गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप से परिवर्तन करने की प्रक्रिया ग्रामीण विकास है। विभिन्न सरकारी कार्यक्रम जो कि ग्रामीण विकास के लिए संचालित है तथा विभिन्न रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित है किन्तु यह व्यवहारिक रूप से सफल तभी हो सकता है जबकि ग्रामीण जनता की बीच सरकार औपचारिक षिक्षा को प्रसारित करने में वृद्धि दर्ज कर सके। षिक्षा स्वास्थ्य एवं गरीबी तीन ऐसे प्रमुख स्तम्भ है जो ग्रामीण विकास में बाधक बने हुए है। षिक्षा एवं स्वास्थ्य को विकसित करना बहुत ही नितान्त आवष्यक है। विकास की धारा में जुड़ने के लिए तीनो स्तम्भों का सुधार करने की जरूरत है तथा रोजगार सृजन हेतु वयस्को को सरकारी कार्यक्रम की जानकारी देना तथा उन्हें उस कार्य हेतु तैयार करना एक बड़ी चुनौती है क्योंकि अषिक्षा ऐसा करने में बाधक बन बैठी है।

सरकारी रोजगार कार्यक्रम का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए अति आवष्यक हे कि गांवो में एक सूचना केन्द्र स्थापित किया जाय तथा सूचना प्रौघोगिकी को अत्याधुनिक तरीके से विकसित किया जाय ताकि ग्रामीणो को उनका लाभ मिल सके वे खुद को रोजगार की धारा में जोड़कर अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाकर विकसित भारत बनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें।

औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण, वैष्वीकरण का स्पश्ट प्रभाव गांवो की सामाजिकता, आर्थिक, सांस्कृतिक संरचना पर देखा जा सकता है। इन सब का सम्मिलित प्रभाव ग्रामीण उपयोग स्तर में वृद्धि के मामले में देखा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रो में उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। इस बढ़ती मांग ने गांवो में रोजगार के नये अवसरो को भी बढ़ाया है। गांवो का भविश्य रोजगार की असीम सम्भावनाओं से युक्त दिखायी पड़ रहा है। आवष्यक है कि इसे बेहतर तरीके से नियमन, संचालन प्रबधन के द्वारा राश्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में ग्रामीण भागीदारी का स्तर उठाया जा सकें।

संदर्भ:–

(प) ूण्पदकपूंजमतचवतजंसण्वतहण्पद

(पप) कुरूक्षेत्र फरवरी 2013, गौरव कुमार

(पपप) तनतंसणूापचमकपंण्वतहण्पद.

(पअ) ूण्हवअण्पद

(अ) डॉ0 वी0एन0 सिंह, डॉ0 जन्मेजय सिंह, ग्रामीण समाज षास्त्रः विवेक प्रकाषन, नई दिल्ली–2008

(अप) विश्णु मोहन दास, भारत में ग्रामीण विकास, नेहा पब्लिकेषन, नई दिल्ली।

(अपप) दैनिक जागरण

(अपपप) कुरूक्षेत्र योजना पत्रिका

;जीपे ·तजपबसम जलचमक पद ज्ञतनजप क्मअ 046द्ध